POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

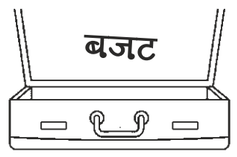

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अप्रेल, 2025 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राज्य विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट रखा। माना जा रहा है, यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने और प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

बजट पर मिली प्रतिक्रियाओं से यह सामने आया है कि इस बार बजट में सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने एवं डेढ़ लाख को निजी क्षेत्र में रोजगार देने, ग्रामीण स्तर तक बुनियादी ढांचे को मजबूती देने, जयपुर में मेट्रो का विस्तार, कृषि को किसानों के लिए लाभप्रद बनाने, महिलाओं को सशक्त व समृद्ध करने के साथ युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, जैसी कई घोषणाएं अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाईयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

हमारी सरकारें ऐसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाती हैं, जो आमजन और देश के विकास में 'मील का पत्थर' साबित हों। लेकिन सही क्रियान्वयन एवं उचित निगरानी नहीं होने से कई सार्थक योजनाएं बीच में ही अधूरी रह जाती हैं।

ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे योजनाएं अपने मकसद को पूरा करने में खरी साबित हो सकें। इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को विश्वास दिलाया कि बजट में की गई घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में 46 फीसदी महत्वपूर्ण योगदान देती है। सतत् विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता आवश्यक है। प्रदेश में आए निवेशकों को निराश नहीं किया जाना चाहिए। मजबूत निगरानी व्यवस्था, कौशल विकास में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास जैसी समग्र रणनीति से मजबूत निवेश वातावरण बनेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

महिलाओं को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए उठाए कई कदम

बजट घोषणा के अनुसार कालीबाई योजना के तहत 35 हजार स्कूटी वितरित की जाएंगी, राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ा जाएगा। पत्नी के नाम से या संयुक्त नाम से खरीदी 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को एक लाख रुपए का ऋण 1.5 प्रतिशत की दर पर मिलेगा। समूहों की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत अंतिम पांच महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दो लाख 35 हजार महिलाओं को फायदा होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब 5 दिन दूध मिलेगा। दो लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भी बजट में महिलाओं को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का किया प्रयास

सरकार ने प्रदेश में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का प्रयास किया है। इसके लिए बजट में 26,697.86 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे राजमार्गों, जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों का तेजी से विकास हो सकेगा। इसमें से ग्रामीण सड़क निर्माण पर 7,150 करोड़ रुपए एवं परिवहन व सड़क सुरक्षा पर 1,271.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

शहरी एवं ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए 8,761 करोड़ और ऊर्जा विकास के लिए 39,576 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रावधान बजट में है। इससे जल जीवन मिशन को तेज गति मिलेगी,गर्मी को देखते हुए 1000 ट्यूबवेल और 500 हैंडपंप भी लगाए जाएंगे। हरित ऊर्जा को खास महत्व दिया जाएगा। बिजली क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरों पर सोलर पेनल लगा, उससे 150 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना है।

कृषि क्षेत्र को मिला बढ़ावा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने खेती और किसानों के विकास के लिए बजट में 14,075.96 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अब सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। इससे 70.36 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

किसानों को दीर्घकालीन कृषि ऋण भी दिए जाएंगे। कृषि उपकरणों पर 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे एक लाख किसानों को फायदा मिलेगा। कृषि मंडियों की दशा सुधारने पर 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को मोटे अनाज और इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त बीज के मिनी किट दिए जाएंगे। बजट में खेती को लाभप्रद बनाने के लिए और भी कई घोषणाएं हैं।

सेहत पर ध्यान, नब्ज पर रखा हाथ

बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कुल मिलाकर 20,324.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जयपुर स्थित एसएमएस व इससे जुड़े अस्पतालों में चिकित्सा व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अपग्रेडेशन व भवन निर्माण के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। इसके लिए हर गांव को 11 लाख रुपए मिलेंगे। जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खुलेंगे व पीएचसी में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगेगी।

शिक्षा से होगी रोजगार तक पहुंच

प्रदेश के बजट में शिक्षा को रोजगार से जोड़ते हुए कुल मिलाकर कौशल पर ज्यादा जोर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेक्टर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। स्कूल, कॉलेज में सीटें बढ़ेंगी। 1500 स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब बनेंगे।

रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए सरकार युवाओं के लिए रोजगार नीति 2025 लाएगी। प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्केलिंग एंड कैरिअर काउंसलिंग की स्थापना होगी। 8 नई व 36 पुरानी आइटीआर का नवीनीकरण होगा। एआइ जैसी एडवांस तकनीक में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। 12वीं पास कर चुके छात्रों को विशेषज्ञों से कैरिअर गाइडेंस मिलेगा। छात्रों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

सिंचाई व्यवस्था होगी बेहतर

बजट में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके लिए राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागू होगी।

बजट में 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिकलर सिंचाई के लिए 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसानों को 50 हजार सौर पंप संयंत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास को लगेंगे पंख

बजट में ग्रामीण विकास को खास महत्व दिया गया है। इसके लिए 24,925.02 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर 5,277.03 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

बजट में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक लाख 56 हजार आवासों का निर्माण करने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 85 हजार घरेलू शौचालय व 2500 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। इसके अलावा बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए विशेष ध्यान दिया गया है।

'मां' फंड होगा गठित, बुजुर्गों पर ध्यान

निःशुल्क जांच व दवा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का 'मां' फंड गठित किया जाएगा। योजना में अब प्रदेश के बाहर भी इलाज कराने की सुविधा मिलेगी।

70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से केयर पैकेज बनेगा। उन्हें सुविधानुसार घर पर निःशुल्क दवा मिलेगी। उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज भी जुड़ेंगे। इसके अलावा ट्रक-बस ड्राइवरों सहित अन्य कामगारों के लिए भी 'मां' नेत्र वाउचर योजना की घोषणा की गई है।

स्कूली शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन

बजट में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 40,992 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 50 प्राथमिक स्कूलों को आठवीं कक्षा तक व 100 स्कूलों को उच्च माध्यमिक विधालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

स्कूलों में लैब, क्लास रूम, कम्प्यूटर लैब और टॉयलेट आदि का निर्माण कराया जाएगा। गंगानगर में सैनिक स्कूल व पांच जिलों में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित होंगे। 15 हजार विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा के लिए 1,552 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हैं।

औद्योगिक समस्याएं दूर करने पर जोर

बजट में औद्योगिक विकास के लिए 3,121.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश को लॉजेस्टिक हब बनाने, वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अहमियत देने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से जहां उद्यमियों को लाभ मिलेगा, वहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

बजट में औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार की नीति, जिला स्तर पर पनप रहे उद्योगों को संबल देने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा अन्य समस्याओं के निदान से राज्य में निवेशक आकर्षित होंगे और नए उद्योग खुलेंगे। बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

पशु पालकों के लिए कई सुविधाएं

बजट में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए पशु अनुदान की राशि में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में 200 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। सौ पशु चिकित्सक एवं एक हजार पशुधन निरीक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख 50 हजार पशुपालकों को ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना किया जाएगा।

बजट में अन्य राहतभरी खास घोषणाएं

- 70 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को घर पर दवा आपूर्ति करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 750 डॉक्टरों और 1500 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इस साल 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से व 50 हजार को एसी ट्रेन से तीर्थयात्रा कराने का प्रावधान है।

  कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 2.10 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस साल में 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोडा जाएगा।
- ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। गांवों को सड़क-रेलवे से जोड़कर उनका प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित हों। इससे गांवों में नए रोजगार पैदा होंगे। 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक धार्मिक और इको टूरिज्म साइट्स के विकास कार्यों के लिए सौ करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा। इसमें बांसवाड़ा जिले की त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़धाम, प्रतापगढ़ का सीतामाता अभयारण्य एवं गौतमेश्वरजी, उदयपुर के ऋषभदेवजी, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया आदि को शामिल किया गया है।
- भीलवाड़ा क्लीन व ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित होगा। कोटा में 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट बनेगा। जोधपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर खुलेगा।

  धौलपुर में चंबल लिफ्ट के लिए 950 करोड़ रुपए की घोषणा की गई हैं। बीकानेर साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में संभागवार स्तर पर कई विकास कार्य किए जाने के प्रस्ताव बजट में शामिल हैं।
- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर (टोडी मोड़ तक) तक जयपुर मेट्रो अब जल्द तेजी से राह पकड़ेगी। करीब 23 किमी लंबे इस रूट वाली मेट्रो के लिए सरकार ने बजट में 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अभी मेट्रो बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के बीच चल रही है।

निगरानी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के बजट में और भी कई महत्वपूर्ण एवं राहत देने वाली घोषणाएं की हैं। 'ग्राम गदर' में समय-समय पर शहरों व गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कद्दू' जयपुर